



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1972/अग्राहायणा 4, 1894
No. 263] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1972/AGRAHAYANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th November 1972

SUBJECT—Sale of goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair 1972, New Delhi.

No. 170-ITC(PN)/72.—Customs clearance permits have been issued for import of goods by foreign participants for display at the Third Asian International Trade Fair 1972 being held in New Delhi from 3rd November, 1972 to 17th December, 1972. These customs clearance permits carry a condition to the effect that the goods shall be re-exported within a period of 6 months after the close of the exhibition Third Asian International Fair).

2. The c.i.f. value of the goods allowed to each foreign participants does not normally exceed US. \$ 50,000 which is the maximum value of the 'Fair Quota' initially fixed for the purpose. In such cases, the imported goods can be sold by foreign participants directly to actual users holding valid import licences for the goods in question. The actual users willing to purchase these goods should approach the Chief Controller of Imports & Exports. They should produce both the copies of the licence, namely, Customs Purposes and Exchange Control, and 3 copies of the list of items covered by their licence, which they have agreed to purchase from the foreign participants. The list of items should indicate the description of the goods, their quantity and the value in respect of each item. They should also furnish the number and date of the CCP issued to the foreign participant against which the goods sought to be purchased were imported. The Chief Controller of Imports & Exports will endorse the licence suitably, making it invalid for direct imports to the extent the goods covered by the licence are to be purchased from the

foreign participants. Payments for goods purchased from the Trade Fair against valid import licences will be made as usual through the banking channels. The price to be settled between the foreign participant and the actual user purchasing these goods should not exceed the c.i.f. value of the goods.

3. There was also a provision permitting the foreign participants to import goods of a value higher than the initial 'Fair Quota' of U.S. \$ 50,000. This facility which has been availed of by some foreign participants was subject to the condition that the goods will be re-exported within a period of 6 months after the close of the exhibition. In such cases also, the imported goods upto a value not exceeding U.S. \$ 50,000 can be sold by foreign participants directly to actual users holding valid import licences for the goods in question. The procedure for sale will be the same as indicated in paragraph 2 of this Public Notice.

4. The sale of goods in excess of U.S. \$ 50,000 but subject to the participant's quota, will be allowed in such cases either to the State Trading Corporation, New Delhi or to actual users holding valid import licences through the State Trading Corporation. If the purchaser is an actual user holding a valid import licence for the goods, in question, the request for endorsement on the licence should be made through the State Trading Corporation to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. The price to be settled between the foreign participant and the S.T.C. should not exceed the c.i.f. value of the goods. If the goods are purchased by the STC for stock and sale purposes, their request for the grant of import licence will be considered by the Chief Controller of Imports & Exports provided the goods in question are permissible for import under the normal import policy in force and subject to the indigenous clearance given by the DGTD. If any part of the participant's quota remains unutilised and the State Trading Corporation is not willing to take over the goods, it will then be open to the foreign participant to find out an actual user buyer directly holding a valid import licence, in which case the procedure indicated in para 2 above will be valid.

5. It may be clarified that all these transactions for sale will be within the 'quota' as determined by the Fair authorities.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1972

विषय :—1972 के तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, नई दिल्ली में विदेशी हिस्सेदारों द्वारा 'आयातित माल का विक्रय ।

संख्या 170-आई०टी०सी०(पीएन)/72.—3 नवम्बर, 1972 से 17 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में लगने वाले 1972 के तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेले में विदेशी हिस्सेदारों द्वारा प्रदर्शन के लिए माल के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किए जा चुके हैं। इन सीमाशुल्क निकासी परमिटों के साथ एक शर्त इस संबंध में लगाई है कि प्रदर्शनी (तृतीय एशियाई विश्व मेला) के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि के भीतर इन माल का पुनः निर्यात किया जाएगा ।

2. प्रत्येक हिस्सेदार के लिए स्वीकृत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य सामान्यतः 50,000 अमरीकी डालर से ज्यादा नहीं होता जो प्रारम्भिक रूप से इस कार्य के लिए निष्चित किया गया "केयर कोटे" का अधिकतम मूल्य है। ऐसे मामलों में, विदेशी हिस्सेदारों द्वारा आयातित माल का सीधे विक्रय विषयाधीन माल के लिए वैध लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोक्ताओं को नहीं किया जा सकता। इन माफ़ी के खरीद करने की इच्छा रखने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से मंत्रक स्थापित करना चाहिए। उन्हें लाइसेंस की दोनों प्रतियाँ अवधि सीमाशुल्क

प्रयोजन तथा मुद्रा विनियम प्रतियां तथा उा शर्तों की सूची की तीन प्रतियां जिन मद्रों को वे विदेशी हिस्सेदारों से खरीदने के लिए सहमत हुए हैं और अपने लाइसेंस में शामिल किए हैं, प्रस्तुत करनी चाहिए। मद्रों की सूची में माल के व्योरे, उनकी मात्रा तथा प्रत्येक माल के सम्बन्ध में मूल्य का संकेत होना चाहिए। जो माल आयात किए गए थे उनकी खरीद किए जाने वाले माल के लिए विदेशी हिस्सेदारों को जो सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया गया था उसकी संख्या तथा दिनांक भी देना चाहिए। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लाइसेंस का पृष्ठोक्त उन मान के लिए जो विदेशी हिस्सेदारों से खरीदे जाने वाले हैं, लाइसेंस के अन्तर्गत जाने वाले माल की सीमा तक के लिए सीधे आयात के लिए वैध करते हुए उचित तरीके से करेंगे। वैध आयात लाइसेंसों के मद्दे व्यापार मेने से खरीद किए जाने वाले माल के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से किया जाएगा। विदेशी हिस्सेदार तथा वास्तविक उपयोक्ता के बीच इन मालों की खरीद के लिए निश्चित की गई कीमत माल की लागत बीमा भाड़ा मूल्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अमरीकी डालर 50,000 के प्रारंभिक "फेयर कोटे" से अधिक मूल्य के माल का आयात करने के लिए विदेशी हिस्सेदारों को अनुमति देने की व्यवस्था थी। यह सुविधा जो कुछ विदेशी हिस्सेदारों के लिए वैध की गई है वह इस शर्त के अधीन थी कि प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि के भीतर माल का पुनः निर्यात किया जाएगा। ऐसे मामलों में भी, आयातित माल का मूल्य अमरीकी डालर में 50,000 से अधिक नहीं है, तो विदेशी हिस्सेदारों द्वारा ऐसे माल का विक्रय विषयाधीन माल के लिए वैध आयात लाइसेंस धारण करने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं से सीधे ही किया जा सकता है। विक्रय के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसाकि इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 में संकेतित है।

4. ऐसे माल का विक्रय जिनकी कीमत अमरीकी डालर ; 50,000 से ज्यादा है किन्तु हिस्सेदार के कोटे के अधीन है तो ऐसे माल में या तो राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को या उन वास्तविक उपयोक्ताओं को किया जाएगा जो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वैध आयात लाइसेंस धारण किए हुए हैं। यदि खरीददार विषयाधीन माल के लिए वैध आयात लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोक्ता है, तो लाइसेंस पर पृष्ठांकन के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को आवेदन किया जाना चाहिए। विदेशी हिस्सेदार तथा राज्य व्यापार निगम के बीच निश्चित की जाने वाली कीमत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि राज्य व्यापार निगम द्वारा माल की खरीद स्टॉक के लिए और विक्रय खरीद के लिए की जाती है, तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन के आवेदन पत्रों पर विचार मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि विषयाधीन माल लागू सामान्य आयात निति के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेल्य है और डी० जी० टी० डी० द्वारा दी गई देशी निकासी के अधीन है। यदि हिस्सेदार के कोटे का कोई भाग बिना उपयोग किए जा बच जाता है और राज्य व्यापार निगम माल का लेने के लिए इच्छुक नहीं है, तो विदेशी हिस्सेदार के लिए स्वतंत्रता होगी कि सीधे ही ऐसे वास्तविक उपयोक्ता खरीददार की खोज करे जो आयात लाइसेंसधारी है। इस मामले में उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित प्रक्रिया वैध होगी।

5. इसे स्पष्ट कर लिया जाए कि विक्रय के लिए ये सभी सौदे मेल प्राधिकारियों द्वारा बंधा निरधारित 'कोटे' के भीतर है।

एम० एम० सी०

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

